2(8)

3

No.7/6/2013-Bud./237
Government of India
Ministry of Water Resources
*****

New Delhi, dated 12th June 2013

Office Memorandum

Sub: Sectoral Allocation of funds and Allocation of funds under new schemes:-reg.

The undersigned is directed to enclose herewith a copy of Department of Economic Affairs (MoF)'s O.M. No. F.7(1)-B(AC)/2013 dated 03.06.13 on the subject cited above for information, necessary action and compliance.

Encl:As above.

(Vijay Srivastava)
Under Secretary (FD-I)
Tel: 2371 9302

To

JS(A)/ADG(Stat)/JS(PP)/Advisor(NWM)/Commr(SP)/Commr(Indus)/Commr(B&B)/Commr (Pen.Riv.)/Commr(Ganga)/Advisor(Eco.)/CA, MoWR

Copy To:

i. Sr.PPS to Secy (WR)
ii. PPS to Spl. Secy (WR)
iii. PPS to JS &FA (WR)

No. F.7(1)-B(AC)/2013
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Budget Division)
...

New Delhi
3rd June, 2013.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Sectoral Allocation of Funds and Allocation of funds for new schemes.

While examining the Demands for Grants (2013-2014) of Ministry of Finance, the Standing Committee on Finance have observed, in their 67th Report, as follows:

(i) SECTORAL ALLOCATION OF FUNDS:

The Committee have noted with concern that allocated funds are not being fully utilized even though there are resource constraints. With regard to better utilization of funds, the Committee recommend that necessary corrective measures be initiated to augment the absorptive capacity of the line Ministries so that the allotted funds are fully utilized leaving no scope for any downward revision in funding.

(ii) ALLOCATION OF FUNDS FOR NEW SCHEMES:

The Committee express their extreme disappointment over the provision of huge/token amount without preparatory work/ finalization of schemes. The Committee would, therefore, urge upon the Ministry to review the allocations for the new schemes without specific details about objective, targets, allocations and mechanism for implementation while exploring to strengthen the ongoing schemes by way of merger/streamlining/rationalization etc.

2. All Ministries/Departments are, therefore, requested that necessary corrective measures may be initiated for obtaining timely approval of the competent authority and for review of the progress of the schemes handled by the Ministry/Department periodically so that the allotted funds are fully utilized in a phased manner. This would facilitate maintaining the budget provision approved by Parliament in the mid year review. Similarly, Ministries/Department are also requested that funds for new schemes including token provisions may not be made without finalizing the specific details about objectives, targets, allocations and mechanism for implementation of the proposed schemes without approval of competent authorities viz. SFC/EEC, etc., in their Demands for Grants. Efforts may also be taken for strengthening the ongoing schemes by way of merger/streamlining/rationalization etc.

04/06/2013

(Dr.Rajat Bhargava)
Joint Secretary (Budget)

To

All Financial Advisors of Ministries/Departments.
Ministry of Water Resources

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बजट प्रभाग)

नई दिल्ली, 3 जून, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- निधियों का क्षेत्रवार आबंटन और नई स्कीमों के लिए निधियों का आबंटन।

वित्त मंत्रालय की अनुदानों मांगों (2013-14) की जांच करते समय, वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 67वीं रिपोर्ट में यह पाया कि:-

(i) निधियों का क्षेत्रवार आबंटन:

समिति ने गंभीरतापूर्वक नोट किया कि स्रोतों के सीमित होने के बावजूद आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। निधियों के बेहतर उपयोग के संबंध में, समिति ने सिफारिश की है कि संबंधित मंत्रालयों की समावेशी क्षमता में बढोत्तरी के लिए सुधारात्मक उपाय शुरु किए जाएं ताकि आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग किया जा सके जिससे निधियों में कटौती की कोई गुंजाइश न रहे।

(ii) नई स्कीमों के लिए निधियों का आबंटन:

प्रारंभिक कार्य/ स्कीमों को अंतिम रुप दिए बिना बड़ी/ सांकेतिक राशि के प्रावधान के संबंध में समिति ने गहरी निराशा व्यक्त की। अत: समिति मंत्रालय से आमेलन/सरलीकरण/यौक्तिकरण आदि के द्वारा चल रही योजनाओं की सुदृढ़ीकरण संबंधी संभावनाओं का पता लगाते समय उद्देश्य, लक्ष्य, आवंटन, कार्यान्वयन तंत्र के बारे में स्पष्ट ब्यौरे से रहित नई स्कीमों के लिए आवंटनों की समीक्षा करने का अनुरोध करेगी।

2. अत: सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेने और मंत्रालय/विभाग द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की प्रगति की आवधिक समीक्षा के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई समय पर की जाए ताकि आवंटित निधियों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ण उपयोग किया जा सके। इससे संसद द्वारा मध्यावधिक समीक्षा में अनुमोदित बजट प्रावधान को बनाए रखने में सुविधा होगी। इसी प्रकार, मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि अपनी अनुदान मांगों में उद्देश्य, लक्ष्य आबंटन तथा कार्यान्वयन तंत्र आदि रहित प्रस्तावित स्कीमों आदि के विनिर्दिष्ट ब्यौरों को अंतिम रूप दिए बिना और सक्षम प्राधिकारियों अर्थात् एसएफसी/ईईसी आदि के अनुमोदन के अभाव वाली नई योजनाओं के लिए, सांकेतिक प्रावधान सहित, निधियों का आवंटन न किया जाए। साथ ही चल रही योजनाओं के आमेलन/सरलीकरण/यौक्तिकरण आदि के द्वारा उनके सुदृढ़ीकरण के प्रयास भी किए जाएं।

रजत भार्गव
04.06.2013

(रजत भार्गव)
संयुक्त सचिव (बजट)

सेवा में,
मंत्रालयों/विभागों के सभी वित्तीय सलाहकार।